position for the three Services is given below:-

	Officers	Personnel below officer rank
Army	12,972	55,263
Navy	690	2,782
Air Force	1,045	5,876

The Fifth Central Pay Commission has recommended improvement in pay scales allowances and service conditions of the Service personnel so as to help attract youth in larger numbers to opt for a career in the Armed Forces. The Commission has also made, inter-alia, the following suggestions:—

(i) A starting salary of Rs. 8250/- p.m. for commissioned officers of the Armed Forces giving them an edge over the civilian services. Cadets during the period of training Service Academies may be given a stipend of Rs. 8000/ p.m. against the existing stipend of Rs. 1500/- p.m. granted in the last six months of training.

(ii) Efforts may be made by the Armed Forces to give wide publicity through the media highlighting the advantages and special benefits available in the career in Armed Forces.

(iii) Students from Military Schools and Sainik Schools may be considered for direct entry into the Armed Forces.

(iv) Armed Forces may conduct a review of the strength of Services officers on deputation and permanent secondment to other organisations.

(v) An increase in the reservation quota for ex-service personnel in Central Police Organisations.

(vi) Grant of assured career promotion scheme to officers and personnel below officer rank (PBOR).

(vii) Reduction in time taken for substantive promotion of Service officers.

(viii) Increase in weightage in qualifying service for pension etc. etc.

The recommendations of the Pay Commission are under consideration of the Government. Meanwhile, Government will soon launch an image projection campaign for the Army to attract the youth by highlighting the positive features of the Army.

Irregularities in Purchase of Digital Exchanges

*459. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether any irregularities have been pointed out by the CAG in regard to purchases of digital exhanges worth Rs. 600 crores by India from multinationals;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) Yes, Sir. The CAG has pointed out certain irregularities in procurement of switching equipment in his report for the period ending 31st March, 1996.

(b) The details thereof are as follows:

(i) 8.9 lakh lines of equipment was purchased by the DOT based on a tender for only 2 lakh lines.

(ii) Excess lease payment of Rs. 30.75 crores over a period of 8 years due to failure to take into consideration the reduction in custom duty in 1994-95 Budget. Besides, avoidable

payment of Rs. 10 lakhs towards management fees.

(iii) Loss of potential revenue of Rs. 19.73 crores due to delay in supplies coupled with deficient project management.

(iv) Payment of lease rental of Rs. 7.18 crores in advance before completion of supplies.

(v) Non-utilization of switching capacity to optimum level.

(vi) Irregular payment of Sales Tax and Octroi by certain units.

(c) The irregularities pointed out by the CAG are under examination by the DOT.

पुलिस थानों को जोड़ने के लिए "पोलनेट" परियोजना

*460. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश में सभी जिला पुलिस थानों को पुलिस मुख्यालयों से जोड़ने के लिए उपग्रह दूरसंचार प्रणाली "पोलनेट" का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवें वित्त आयोग ने राज्य को आवश्यक धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए "पोलनेट" परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्ता): (क) से (छ) "पोलनेट" परियोजना का ध्येय, एक उपग्रह आधारित संचार प्रणाली के माध्यम से वर्तमान पुलिस संचार प्रणाली का उन्नयन करना है। इस परियोजना से देश में पुलिस बलों को वॉयस / डाटा / फैक्स और कम्प्यूटर संचार पर अति विश्वसनीय, तीव्र गतिशील और अबाध संचार उपलब्ध होगा।

प्रस्ताव में पुलिस के लिए दूरसंचार विभाग से एक उपग्रह ट्रांसपोन्डर किराए पर लेकर इससे 833 वी-सैट्स को जोड़ने की बात की गई है ताकि जरूरत के आधार पर एक दूसरे के साथ वॉयस / डाटा / फैक्स पर सीधा संचार कायम किया जा सके। मुख्य भूकेन्द्र (मास्टर अर्थ स्टेशन) नई दिल्ली में अवस्थित होगा और वी-सैट टर्मिनल राष्ट्रीय राजधानी, राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के चुनिंदा अवस्थानों पर अवस्थित होंगे। जिला मुख्यालय स्तर से नीचे पुलिस स्टेशन / सीमा चौकियों को, मौजूदा संचार नेटवर्क पर ही इससे जोड़ दिया जाएगा।

परियोजना की सकल अनावर्ती लागत 137.91 करोड़ रु० है। जहां दसवें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 21 राज्यों के हिस्से की पूर्ति के लिए 77.51 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराने की सिफारिश की है वहीं आयोग ने गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के अंश के वित्तपोषण की सिफारिश नहीं की क्योंकि ऐसा माना गया कि इन राज्यों के पास अधिशेष राजस्व है। इन चारों राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्वयं के संसाधनों से परियोजना हेतु धन उपलब्ध कराएं।

अन्तर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति में योजना का अनुमोदन कर दिया है और गैर-योजनागत व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन मांगा गया है।

इस परियोजना को पूरा करने के लिए तीन वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Opening of new Branch Post Offices in Bihar

3339. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of Branch Post Offices sanctioned and opened district-wise during 1995-96 and 1996-97 in Bihar;